the payment of loans by fixing the price of land?

Shri Shyam Dhar Misra: It is a fact that there have been delays even now. I cannot claim that there is no delay in the scrutiny of applications and payments. One reason has been that it takes quite some time to verify the records for 23 to 24 years. Now it has been suggested to the land mortgage banks that the records may be verified only for twelve years and then loans may be advanced. Similarly other suggestions have also been made to the land mortgage banks and they are acting on them.

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सिस्टम में किसान की जो मौजूदा खड़ी हुई फसल हैं, वे अभी शामिल की जाती हैं या नहीं ?

श्री श्यामधर मिश्र : लैंड मार्गेज बैंक्स में लैंड शामिल की जाती है । प्राडक्शन पर्पिजिज के लिये. . . .

Mr. Speaker: Are the standing crops also taken into consideration?

Shri Shyam Dhar Misra: No, not the standing crops.

श्री कछवाय : क्या यह सच है कि काश्तकारों को पैसा मिलने में काफी समय लगता है और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ? वह समय कब आएगा, जब कि उन को आसानी से पैसा मिल सकेगा?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो आ चुका है ।

श्री श्यामधर मिश्र : आशा है कि. . .

Mr. Speaker: I would not allow a supplementary and yet the Minister takes cognisance of it.

श्री बड़े: क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्राइमरी बक्स होते हैं, उन का रवैया यह है कि जो किसान कर्जे में रहता है, उस से केवल लैंड ही नहीं, बल्कि और भी सिक्यूरिटी ली जाती है, स लिए बक फल हो रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र: ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सिक्यूरिटी उन के पास हो कर्जे के लिए, चाहे लैंड हो और चा कोई चीज हो, उन को कर्जा मिलना चाहिए ।

Indo-Swiss Air Agreement

*307. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether any alterations/modifications in the Indo-Swiss air-pact have been recently agreed upon between India and Switzerland; and

(b) if so, the modifications affected in the previous agreement?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Mohiuddin): (a) Yes, Sir.

(b) Modifications have been made in respect of the Annex to the India-Switzerland Air services Agreement to provide for more detailed and comprehensive route schedules for operation of air services by the designated airlines of India and Switzerland.

Shri P. C. Borooah: What were the main reasons for the modification of the agreement?

Shri Mohiuddin: Under the old agreement of 1945 the route schedule was very restricted. Now it has been provided that the Indian airlines on one side and the Swiss airlines on the other can adopt more flexible routes.

Shri P. C. Borooah: What is the average weekly passenger and goods traffic between the two countries and what is the additional expected income and expenditure per year as a result of these modifications?

Shri Mohiuddin: The modification of this agreement is not meant for any direct additional income or additional traffic. Of course, as far as the Air India's traffic between India and Europe is concerned, the hon. Member can have the details from the annual report.

Shri Joachim Alva: We have entered into air agreements with a dozen countries. Do we follow uniform rules or the rules laid down by the International Civil Aviation Organisation or do we have the most-favoured nation treatment with some countries?

Shri Mohiuddin: The agreements are bilateral agreements. Broadly speaking, they are as far as I can remember more or less uniform with the many countries. Of course, there are minor details and other details which differ from one country to another.

उपभोक्ता सरकारी स्टोर

+

*३०८. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गो० महन्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे थोक माल बेचने वाले उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को प्रोत्साहन दें ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसे कितने स्टोर खोलने का विचार है ; और

(ग) इनको किस प्रकार का माल रखने की सलाह दी गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजना के अधीन १९६३–६४ के अन्त तक २०० थोक भण्डार और ४,००० प्राथमिक भण्डार-शाखाएं गठित की जानी हैं ।

(ग) भण्डारों को सामान्यतः खाद्यान्न, कपड़े और दूसरी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं रखने की सलाह दी गई है ।

[(a) Yes, Sir.

(b) The centrally sponsored scheme for consumers co-operatives envisages organisation of 200 wholesale stores and 4,000 primary stores.branches by the end of 1963-64.

(c) The stores have been advised to deal generally in foodgrains, cloth and other essential consumer goods.]

श्री नवल प्रभाकर : मैं जानना चाहता हूं कि इनको जो होलसेल प्राइस पर माल दिया जाता है वह क्या उचित मूल्य पर मिल जाता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : बहुत सी चीज़ें तो होलसेल प्राइस पर मिल जाती हैं और जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जैसे कुछ प्राइवेट आर्गेनाइजेशन्ज़ नहीं दे रही हैं, उनके बारे में सरकार कोशिश कर रही है कि उनको दी जायें । गल्ला वगैरह और कपड़ा वगैरह उचित मूल्य पर और थोक मूल्य पर मिल जाता है ।

Shri P. C. Borooah: May I know whether there is any provision for subsidy to these stores; if so, in what